जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है देश का नया मैन्युफैक्चरिंग हब

3600 हैक्टेयर भूमि पर विकसित हो रहा है औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक टाऊनशिप बनेगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि राजस्थान में बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं, जो पूर्ण इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में उभरें। इन टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस के साथ-साथ लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग तथा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सभी आवश्यक सहायक सेवाओं का समावेश हो, ताकि ये क्षेत्र अपने आप में आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्र बन सकें।

- देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान, अब देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में उभर रहा है। पचपदरा में शुरू होने जा रही रिफाइनरी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने के बाद तथा अमृतसर-जामनगर हाईवे समेत तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण यह क्षेत्र वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है।
- इस औद्योगिक टाउनशिप में भविष्य में कुल 1200 से अधिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है, जिनसे वर्ष 2042 तक लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसी सोच के अनुरूप जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र लगभग 3600 हैक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप के रूप में स्थापित होगा और प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। इस औद्योगिक क्षेत्र में बडे पैमाने पर निवेश के साथ-साथ हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय व क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ आधार मिलेगा।

डीएमआईसी परियोजना विकसित करने के लिये राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडर्स डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जोकि एक एसपीवी है, का गठन किया गया है जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से रीको की 51 प्रतिशत अंशपूंजी है तथा भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास कार्यान्वयन ट्रस्ट की 49 प्रतिशत अंशपूंजी है।

पश्चिमी राजस्थान अब देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में उभर रहा है। पचपदरा में शुरू होने जा रही रिफाइनरी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने के बाद तथा अमृतसर-जामनगर हाईवे समेत तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण यह क्षेत्र वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है।

यह निवेश क्षेत्र दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण नोड है। इसकी रणनीतिक लोकेशन ना सिर्फ उद्योगों की स्थापना के लिये लाभकारी है, अपितु राज्य का सबसे बडा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी यहां स्थापित होने से लॉजिस्टिक्स एवं सर्विस सेक्टर के लिये यह उपयुक्त क्षेत्र साबित होगा। यहां वर्क टू होम कल्चर के लिये विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना विकसित कर आवासीय, वाणिज्यिक एवं रिक्रियेशनल गतिविधियों को अनुमत किया जायेगा ताकि इस औद्योगिक टाउनशिप में काम करने वाले व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र में सारी सुविधायें प्राप्त हो सकें।

यह औद्योगिक टाउनशिप जोधपुर-पाली के मध्य स्थित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गो से बेहतर तरीके से जुडी हुई है तथा हवाई अड्डा भी मात्र 30 किमी की दूरी पर स्थित होने के कारण यह लोकेशन उद्योगों एवं सर्विस सेक्टर को देश के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम बाजारों तक तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिये तथा कच्चे माल की आपूर्ति एवं तैयार माल की ढुलाई के लिये लूणी रोहट मारवाड जंक्शन रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है जिससे सीधे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी हो सकेगी और निर्यात क्षमता बढ़ सकेगी। औद्योगिक टाउनशिप तक सुविधाजनक पहुंच के लिये एनएच-65 पर अंडर व्हीकूलर पास का निर्माण अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है तथा यह मार्च 2026 तक तैयार हो जायेगा जिससे औद्योगिक टाउनशिप तक सरल एवं निर्बाध पहुंच संभव हो सकेगी।

किसी भी निवेश का सबसे बड़ा आधार ऊर्जा एवं जल की निर्बाध आपूर्ति होती है। इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिये सस्ती ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है, इसके लिये राज्य में प्रथम बार विद्युत सप्लाई भी रिडको द्वारा ही की जायेगी।

इसके लिये पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 300 करोड़ से अधिक व्यय किये जा रहे हैं। यहां निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 220 केवी की दोहरी लाईन डाली जा रही है तथा उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर्स लगाये जाएंगे। गैस की उपलब्धता के लिये स्पर लाईन डाली जा रही है।

पानी की आपूर्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा 54 एमएलडी जल आरक्षित किया गया है जिसकी आपूर्ति राजीव गॉधी लिफ्ट केनाल जोधपुर से की जायेगी। आपूर्ति लाईन के लिये पीएचईडी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है जो मौके पर जारी है। जल प्रबन्धन के कार्य के लिये लगभग 175 करोड से अधिक व्यय किया जा रहा है।

इस औद्योगिक टाउनशिप में भविष्य में कुल 1200 से अधिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है, जिनसे वर्ष 2042 तक लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

1578 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले फेज-ए में भारत सरकार द्वारा रूपये 922 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें रूपये 322.80 करोड़ भारत सरकार की अंश पूंजी के रूप में तथा रूपये 105 करोड़ सॉफ्ट लोन के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस फेज के लिये भूमि रिडको को सौंपी गयी है तथा परियोजना क्रियान्वयन के लिए रूपये 193.60 करोड़ रिडको को भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं। चरण-बी की अवाप्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा चरण सी के लिये अवाप्ति प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

आमजन से मुलाकात कर सेहत, दिनचर्या और जीवनशैली से जुड़े विषयों पर बातचीत की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार सुबह जयपुर के जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक किया।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार सुबह जयपुर के जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक किया।

उन्होंने 'फिट राजस्थान-फिट इंडिया' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सभी को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान पार्क में मौजूद लोगों ने भी कदमताल मिलाते हुए मुख्यमंत्री के साथ मॉर्निंग वॉक की। शर्मा ने आत्मीयता के साथ आमजन से मुलाकात की और सेहत, दिनचर्या तथा जीवनशैली से जुड़े विषयों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने जवाहर सर्किल पार्क स्थित मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने जूस पीते हुए आमजन के साथ चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हैप्पीनेस एवं फिटनेस ग्रुप की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉ. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'फिट राजस्थान-फिट इंडिया' का दिया संदेश

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समता और न्याय का जो मार्ग दिखाया है, वह सदैव देश और समाज को प्रगति और सद्भाव की ओर अग्रसर करता रहेगा।

पतंजलि योगपीठ और रूस सरकार के मध्य एमओयू

वैलनेस, योग-आयुर्वेद का रूस में विस्तार, रूस व भारत के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंध तथा स्किल्ड लेबर का आदान-प्रदान करने पर सहमति

नई दिल्ली। पतंजलि समूह तथा रूस सरकार के मध्य दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें पतंजलि समूह की ओर से स्वामी रामदेव तथा मॉस्को सरकार (रूस) की ओर से भारत-रूस व्यापार परिषद के अध्यक्ष एवं रूस के वाणिज्य मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने हस्ताक्षर किए।

कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने कहा कि यह एमओयू स्वास्थ्य एवं वेलनेस का संवर्धन, स्वास्थ्य पर्यटन, कुशल मानव संसाधन का आदान-प्रदान तथा अनुसंधान आदि विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि रूस में योग, आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा को लोग पसंद करते हैं तथा इनका अनुसरण भी करते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हमें ऋषियों की इस वैलनेस विधा को पूरे विश्व के लगभग 200 देशों में पहुँचाना है जिसका एण्ट्री प्वाइंट रूस ही होगा। इस एमओयू के पहला महत्वपूर्ण बिन्दु रूस में पतंजलि की वैलनेस सेवाओं का विस्तार करना है। हम रूस के साथ मिलकर को करने, पर गहन अनुसंधान करेंगे जिससे गम्भीर रोगों का मानव शरीर में आने से वर्षों पहले ही पता किया जा सकेगा। इसका दूसरा बिन्दु भारत के आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति, योग, आयुर्वेद तथा भारत की अमूल्य धरोहरों से संबंधित ज्ञान को रूस के साथ साझा करना है। इसके लिए हम भारत की संस्कृति तथा ऋषियों की धरोहर को रूस लेकर जाएंगे। एमओयू का तीसरा बिन्दु रूस को भारत के द्वारा स्किल्ड लेबर व कुशल योगी उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पतंजलि ही एकमात्र प्राइवेट पार्टनर रहा है। हम रूस को कुशल योगी व कुशल श्रमिक उपलब्ध कराएँगे। साथ ही इस एमओयू के तहत भारत के उच्च स्तरीय ब्रांड्स को रूस में तथा रूसी ब्रांड्स को भारत में प्रोमोट करना है। हम विश्वस्तरीय पतंजलि ब्रांड को रशिया लेकर जाएंगे जिससे पतंजलि के गुणवत्तायुक्त उत्पादों का लाभ रूस के नागरिकों को भी मिलेगा।स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत और रूस मित्र देश हैं। भारत का रूस से इमोशनल कनेक्ट आजादी से पहले भी था और आज भी है। भारत में लोग रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतीन को एक सशक्त ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचानते हैं। उनके शौर्य, वीरता व पराक्रम से पूरा विश्व परिचित है। भारत व रूस की मैत्री से कुछ बड़े लोग खुश नहीं हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में रशिया भारत का मित्र था, है और रहेगा।

पतंजलि समूह तथा रूस सरकार के मध्य दिल्ली में हुए समझौता ज्ञापन पर स्वामी रामदेव तथा मॉस्को सरकार (रूस) की ओर से भारत-रूस व्यापार परिषद के अध्यक्ष एवं रूस के वाणिज्य मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने हस्ताक्षर किए।

- आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भारत और रशिया एक-दूसरे के अभिन्न मित्र देश हैं और रहेंगे : स्वामी रामदेव
- पतंजलि के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बनाएंगे : सर्गेई चेरेमिन

आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भारत व रशिया एक दूसरे के अभिन्न मित्र देश हैं और रहेंगे।

इस अवसर पर सर्गेई चेरेमिन ने कहा कि हम पतंजलि के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पतंजलि के योग, आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेकर हम रूस के लोगों की जीवनशैली परिवर्तित करेंगे और उन्हें निरोगी बनाएंगे।

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के आखिर में बुलाने की तैयारी

राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत, बजट फरवरी में होगा पेश

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के अंत में बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार के संकेतों के अनुसार राज्य का वार्षिक बजट फरवरी में पेश किया जाएगा, हालांकि बजट पेश करने की सटीक तारीख बाद में तय होगी। सत्र की शुरुआत परंपरा के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसके लिए सभी विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल होने वाली प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों और महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत ब्योरा 26 दिसंबर तक भेजने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी बजट सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।

- आंकड़ों में गलती न हो, इसके लिए विभागों को सख्त निर्देश

अभिभाषण के आंकड़ों को लेकर पहले भी विवाद उठते रहे हैं-चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की। इसी कारण इस बार कैबिनेट सचिवालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं कि विकास योजनाओं में किए गए खर्च और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी भेजा जाए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहेराज्यपाल के अभिभाषण को फाइनल करने के लिए शीघ्र ही वरिष्ठ मंत्रियों की एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी।

यह समिति सभी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और अभिभाषण में शामिल किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं को अंतिम रूप देगी। बजट सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही राज्यपाल के पास औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। सत्र की अंतिम तारीख राज्यपाल की स्वीकृति से तय होगी।

वन सेवा के अधिकारी पर फर्जी दिव्यांगता का आरोप

राजस्थान हाईकोर्ट ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, यूपीएससी सचिव, पीसीसीएफ और डीओपी सचिव सहित आरएफएस अधिकारी जगदीप सिंह से जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान वन सेवा के अधिकारी पर सेवाकाल के दौरान सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र हासिल करने और उसके आधार पर पहले सलेक्शन स्केल का लाभ और अब आईएफएस पद पर होने वाली पदोन्नित में इसका लाभ मिलने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है। जिस पर अदालत ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, यूपीएससी सचिव, पीसीसीएफ और डीओपी सचिव सहित आरएफएस अधिकारी जगदीप सिंह से जवाब मांगा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश आरएफएस अधिकारी सरिता कुमारी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि जगदीप सिंह का राजस्थान वन सेवा के अधिकारी के पद पर सामान्य तौर पर चयन हुआ था। उसके पास चालीस फीसदी या अधिक की बेंचमार्क दिव्यांगता भी नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया कि अरण्य भवन में तैनाती के दौरान उन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लिया। याचिकाकर्ता वरिष्ठता सूची में जगदीप सिंह से ऊपर हैं, लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें याचिकाकर्ताओं से पहले सिलेक्शन स्केल का लाभ दिया गया। वहीं अब उन्हें इसी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा में पदोन्नित में लाभ दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर एसओजी में कई प्रकरण दर्ज है और राज्य सरकार भी संदिग्ध अधिकारियों की दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करा रही है। इसके बावजूद जगदीप सिंह की दिव्यांगता को लेकर कोई जांच नहीं की गई। आरएफएस से आईएसएफ पद पर पदोन्नित के लिए जल्दी ही पदोन्नित बोर्ड की बैठक होने वाली है। उसमें भी जगदीप सिंह को दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं से ऊपर माना जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार पहले जगदीप सिंह की दिव्यांगता की जांच की जाए और उसके बाद ही डीपीसी बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

संविदा भर्ती नियमों को अनदेखा कर कर्मचारी को हटाने वाले आदेश पर रोक

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा भर्ती नियम की अवहेलना कर चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मी को हटाने वाले आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित संबंधित सीएमएचओ से जवाब तलब किया है। जस्टिस मुनेरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश मोहम्मद फैसल खान पठान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2016 में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में स्वास्थ्य मार्गदर्शक के पद पर संविदा पर लगा था। गत 29 सितंबर को संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि वह राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से नियुक्त हुआ था और संविदा भर्ती नियम के तहत पांच साल की सेवा के बाद नियमित होने का अधिकारी हो गया था। इसके बावजूद उसे झूठी शिकायत पर सेवा से अलग कर दिया गया। जबकि संविदा भर्ती नियम के नियम 18 के तहत किसी संविदा कर्मी के खिलाफ यदि कोई आरोप सिद्ध होता है तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को काम के प्रति लापरवाही बरतने और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाकर सेवा से हटाया गया है, लेकिन इससे पूर्व उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। ऐसे में उसे सेवा से हटाने के आदेश को अवैध घोषित कर निरस्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर की जांच की मॉनिटरिंग करें डीएसपी

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब ढाई साल पहले भरतपुर में सैनी समाज को आरक्षण के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर की जांच की मॉनिटरिंग स्थानीय पुलिस उप अधीक्षक को सौंपी है।

वहीं अदालत ने जांच अधिकारी को कहा है कि वह प्रकरण की जांच करे और यदि जांच में याचिकाकर्ता दोषी पाए जाए तो उसे नोटिस देकर विधि अनुसार आगे की कार्रवाई करे। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश नवल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता वेदप्रकाश सैनी ने अदालत को बताया कि भरतपुर के वैर में 21 अप्रैल, 2023 को सैनी समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। घटना को लेकर पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें याचिकाकर्ता को भी बतौर आरोपी शामिल कर लिया गया।

याचिका में कहा गया कि वह छात्र है और मौके पर मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने उसे मामले में गलत तरीके से फंसा दिया है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में जांच अधिकारी को अभ्यावेदन भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि घटना को लेकर हुई शिनाख्त परेड से साबित है कि याचिकाकर्ता मौके पर ही मौजूद था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में जांच अधिकारी को निर्देश देते हुए डीएसपी को प्रकरण की मॉनिटरिंग करने को कहा है।

फ्लाइट्स रद्द होने से जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान घूमते रहे यात्री

जयपुर। इंडिगो एयरलाइंस की 17 फ्लाइट्स रद्द होने के कारण शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री परेशान घूमते रहे। कई टूरिस्ट ग्रुप भी अटक गए। एयरपोर्ट काउंटर पर सुबह से लंबी लाइनें लगी रही। लोगों का कहना था कि पहले शुक्रवार को फ्लाइट कैंसिल हुई, फिर मैसेज आया कि आज फ्लाइट जाएगी। हम सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो जवाब मिला कि आज की फ्लाइट भी रद्द हो गयी है। अब कह रहे हैं कि बस से दिल्ली चले जाओ। इससे नाराज होकर यात्रियों ने हंगामा भी किया। ज्ञात रहे कि जयपुर से बीते 6 दिन में 81 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की है। लगातार कैंसिल फ्लाइट के कारण जयपुर-मुंबई रूट पर दूसरी एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। शनिवार को मुंबई के लिए किसी भी फ्लाइट में सीट उपलब्ध नहीं थी। रविवार को स्पाइसजेट की दोनों उडानों शाम 6:15 बजे और रात 11:20 बजे का किराया बढ़कर 37 हजार 977 रुपए तक पहुंच गया।